[Shri Santosh Bagrodia]

for Kharif sowing during the current year was 118.85 lakh hectares against which total area under sowing up to 22nd July, 1991 was only 20.70 lakh hectares which is only 17 per cent of the area under sowing last year. Area sown upto last year in this period was 91.69 lakh hectares against which sowing in 20.70 lakh hectares only has been done with a carrying deviation area sown last year (—) 77.4 per cent.

The Government of India has changed the norms of relief in terms of money to be provided as relief to the State. A fixed amount of Rs. 124 crores is provided as Calamity Relief Fund by the Government of India every year. Out of Rs. 124 crores, for the year 1991-92 Rs. 46.50 crores have already been received from the Government of India and Rs. 15.50 crores is the contribution of the State Government. It would appear that in normal conditions the amount so received every year from the Government of India will meet the requirements of the State, but drought conditions in Rajasthan are an abnormal phenomenon. The extent of abnormality increases every third year with drought conditions prevailing in the State and in such a situation the amount allotted to the State to the limit of Rs. 124 crores may not be sufficient to meet the demand of the situation. For example, if we take the amount incurred on famine-relief works under drought conditions in the following years, it will make amply clear that the amount which has been given to the State Government will be totally insufficient to meet the expenses incurred on relief works:

Year	*Amount incurred*
1986-87	Rs. 172.11 crores
1987-88	Rs. 630.28 crores
1988-89	Rs. 330.11 crores

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please be brief; otherwise, others will suffer.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Just a second. I am concluding The norms for allocation of drought relief to Rajasthan may be changed in comparison to natural calamities in other parts of the country. This year I request the Government of India to grant at least as much as that granted last year, i.e., Rs. 330 crores. Thank you.

SHRI B. L. PANWAR (Rajasthan): Madam, I associate myself with Shri Santosh Bagrodia. In Rajasthan, even drinking water is not there. So an additional fund should be given by the Centre to the State Government to meet the situation.

Demand for starting special programmes and conferment of "Bharat Ratna" on Maulana Abul Kalaam Azad and Netaji Subhash Chandra Base during Golden Jublee year of 'Quit India Movement'

श्री प्रमाद महाजन (महाराष्ट्र) : उपसभापति महोदया, आज सत्र का अंतिम दिन है और परसों 9 अगस्त को भारत छोडो दिन है । लेकिन इस वर्ष भारत छोड़ो दिन की एक विशेषता है । यह भारत छोड़ो आन्दोलन का स्वर्ण जयन्ती वर्ष है । हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा छेड़ा गया भारत छोड़ो आंदोलन हमारे स्वाधीनता आंदोलन का सबसे संघर्षमय सफलतम पर्व था । इसी के कारण अंग्रेजों को अन्तिमतः भारत छोड़ना पड़ा । मौलाना अबुल कलाम आजाद उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे । महात्मा गांधी द्वारा भारतीय जनता को दिये गये "करो या मरो—डू आर डाई" के इस आदेश के कारण ही उन्होंने अंग्रेजों को भारत छोड़ो का आदेश दिया तथा उसमें सफलता मिली । यह भारत छोड़ो आंदोलन का स्वर्ण जयन्ती वर्ष है । हम सब को इस वर्ष को बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिये । मुझे इस बात का आनन्द है कि महाराष्ट्र सरकार की ओर

से और वहां के स्वतंत्रता सेनानियों की ओर से कुछ कार्यक्रमों का आयोजन 9 अगस्त से प्रारंभ होगा। लेकिन उसके साथ मुझे इस बात का खेद है कि केन्द्रीय सरकार की ओर से इस स्वर्ण जयन्ती अवसर की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है, न किसी समिति का निर्माण किया है, न कोई कार्यक्रम की योजना की है। हो सकता है कि 'विदेशियों की गुलामी, "भारत आओ" "कम इंडिया" का यह जो आर्थिक वायुमंडल बना है, इसमें शायद हम "क्विट इंडिया" को भूल गये हों। इस लिये मैं इस विशेष उल्लेख के माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि जब हिन्दुस्तान के स्वतंत्रता आंदोलन का यह सबसे स्वर्णिम पर्व था, लड़ाई की दृष्टि से, तो इसके लिये केन्द्र सरकार एक समिति का गठन करे, कुछ विशेष कार्यक्रम ले। मैं जानता हूं इसके पहले भी डाक तार विभाग की ओर से इस पर टिकट जारी किया गया था लेकिन यह स्वर्णिम जयंती अवसर होने के कारण एक विशेष डाक टिकट भी इसके लिये जारी किया जाय।

दूसरा बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन की मांग है जो आज तक वैसे ही परिलंबित पड़ी है। इसलिये इस 9 अगस्त को जो स्वर्णिम जयन्ती वर्ष है, भारत छोड़ो आंदोलन का; इसमें क्या हम यह निर्णय ले सकते हैं कि इस वर्ष के समाप्त होने के पहले हिन्दुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा जिसको इसके प्रति शिकायत हो। उसके साथ-साथ जैसे हमने स्वतंत्रता आंदोलन के कार्यक्रम में किया था क्या हम इस भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर स्वतंत्रता सेनानियों को जिनकी संख्या कम है, आयु ज्यादा है, किसी नयी योजना के अन्तर्गत अधिक रुपया दे सकते हैं? इन सारी चीजों का विचार करके, जैसा कि मैंने कहा, परसों से ही कार्यक्रम शुरू हो सकता है। इसलिये भारत सरकार तुरन्त इस पर विचार करे, यह भारत सरकार से मेरी इस उल्लेख के द्वारा मांग है।

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): Madam, I fully associate with him. I am one of those who took part in the Quite India Movement. I feel that, as Maharashtra Government has done, the Central Government should also organise the same kind of things and awaken the people regarding the integrity and oneness of the country. This type of programmes should be organised so that the people of India would think that we are one people and the country is one. On that line some programmes should be chalked out so that the younger generation and all of us can draw inspiration from that and we shall try to see that India becomes very strong and united.

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार) : मैं एसोसिएट करता हूं।

उपसभापति : मैं आपको बुलवा दूंगी। एक-एक करके होगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।

SHRI N. K. P. SALVE (Maharashtra): Madam, I associate entirely with the very patriotic and very noble demand made by Pramodji. It is heartening to see him take the names of Maulana Abdul Alaam Azad and Gandhiji with such reverence. I congratulate him very much.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: I have all the respect for both these personalities right from the beginning of my life.

SHRI N. K. P. SALVE: I am extremely delighted and I congratulate you.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE (Maharashtra): Madam, I associate myself with him.

श्री चतुरानन मिश्र : उपसभापति महोदया, जो अभी माननीय सदस्य ने कहा मै उसका पूरा समर्थन करता हूं। इस बार हम लोगों ने इसकी योजना बनाई है। मै भी फ्रीडम फाइटर हूं

[श्री चतुरानन मिश्र]

और 1942 के आंदोलन मे "क्विट इंडिया मूवमेंट" में मैने हिस्सा लिया था । बिहार मे हम लोगों ने फ्रीडम फाइटर्स एसोसिएशन की ओर से पूरा इसकी योजना बनाई है । जहां-जहां गोली चली, जहां-जहां लोग मारे गये, हर जगह हम लोग उनके लिये एक स्मृति बनायेंगे और हर जगह एक आयोजन करेंगे तथा उनके बाल बच्चों को देखेंगे .... (**व्यवधान**)

एक बात मै सिर्फ इसमें जोडना चाहूंगा खासकर इसलिये कि यहां गृह मंत्री जी भी हैं, कि हमारे पास कुछ आर्मी के लोग आते हैं जिन्होंने रिवोल्ट किया था, 1938 से लेकर 1945 के पहले कई जगह आर्मी रिवोल्ट हुये थे । उन लोगों की हालत बहुत खराब है । अंग्रेजों ने तो उनको निकाल दिया कोर्ट मार्शल करके । उन्होंने हम लोगों के ही कहने पर रिवोल्ट किया था । इसलिये ऐसे जो फ्रीडम फाइटर्स के केसेज हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि बाकी सबको किया जाय, मै कहना चाहता हूं कि उनके साथ इनको भी दी जाय । यह तो नहीं कि बार-बार फ्रीडम फाइटर्स जन्म लेंगे । जिन्होंने जन्म लिया था उन्हीं का होगा । इस लिये टाइम बाउंड करके ऐसे केसेज खत्म कर लिये जायें और इनमें अंग्रेजों की फौज में जिन्होंने रिवोल्ट किया था उनको शामिल करके उनको तुरंत रिलीफ दिया जाये ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Murlidhar Chandrakant Bhandare. Yes, I called your name.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Madam, I fully associate with him. I am brief with my words.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Very good.

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार) : उपसभापति महोदया, हमारे साथी श्री प्रमोद महाजन जी ने जो स्पेशल मेंशन किया है, उसके साथ मै एसोसियेट करती हूं और एसोसियेट करते हुए इतना कहना चाहती हूं कि भारत के स्वतंत्रता के संग्राम का जो हमारा इतिहास है, लगभग सौ साल पुराना इतिहास है, अगर उसको हम भुला देंगे, अगर हम अपने अतीत को भुला देंगे तो हमारा वर्तमान कुछ नहीं रहेगा और हमारा भविष्य भी कुछ नहीं रहेगा । इसलिये, यह बहुत अच्छा प्रस्ताव लाये हैं और मै इसका पूर्ण रूप मे समर्थन करती हूं ।

श्री दिग्विजय सिंह (बिहार) : महोदया, मै श्री प्रमोद महाजन जी की बात का पूरा समर्थन करते हुए सिर्फ एक बात आज सरकार से अर्ज करना चाहूंगा कि क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आजाद 1942 में जब यह आंदोलन छेड़ा गया था, तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे और आजादी की लड़ाई के उस श्रेणी के सारे लोगों को करीब-करीब जो बाद में सरकार में आये, उन लोगों को भारत रत्न दिया गया है, मौलाना आजाद अकेले आदमी इस श्रेणी में बच रहे हैं, जिनको भारत रत्न की उपाधि नहीं दी गई है ।

मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि अगर यह स्वर्ण जयन्ती मनाई जा रही है, तो इस मौके पर मौलाना आजाद को भारत रत्न की उपाधि दी जाय ।

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): We all support this.

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मोम अफजल (उत्तर प्रदेश) : मै इसकी ताईद करता हूं ....

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश) : सारा सदन इसका समर्थन करता है ... (**व्यवधान**) मौलाना आजाद को भारत रत्न से सम्मानित किया जाय ।... **व्यवधान**

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव (महाराष्ट्र) : मैं सरकार से प्रस्ताव करूंगा कि सुभाष चन्द्र बोस को भी भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि पं० जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना आजाद के साथ उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। मौलाना आजाद और नेता जी सुभाष चन्द्र बोस दोनों को ही भारत रत्न से सुशोभित किया जाए।

श्री रान नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : श्री प्रमोद महाजन जी ने जो प्रस्ताव रखा है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर गम्भीरता से विचार करके जल्दी एक कमेटी बनाई जानी चाहिये। साथ ही साथ मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे विख्यात स्वतन्त्रता सेनानी, जिनका देश को बनाने में बड़ा योगदान रहा है, उनको निश्चित रूप से भारत रत्न की उपाधि देने के बारे में सरकार को सोचना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ जो प्रमोद महाजन जी ने प्रस्ताव रखा है, अपने को उससे संबद्ध करता हूं।

SHRI MENTAY PADMANABHAM (Andhra Pradesh): At the earliest opportunity the Government should make an announcement conferring Bharat Ratna on the great patriot, Maulana Abul Kalaam Azad.

SHRI N. K. P. SALVE: On behalf of the House I would urge upon you to write to the Prime Minister about what has been stated by the honourable Shri Digvijay Singh regarding conferment of Bharat Ratna on Maulana Abul Kalaam Azad as the sentiment of the House.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The Home Minister is here and I am sure he will convey to the Government the feelings of the House regarding the Quit India Movement and giving Bharat Ratna to Maulana Azad and also to Subhas Chandra Bose.

SHRI N. K. P. SALVE: I am sure the Home Minister will do it. But on behalf of the House we urge upon you, we implore you, to convey our sentiments to the Prime Minister yourself and that would be in the fitness of things. I hope you will oblige the whole House.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Considering the sentiments of the House I agree to write a letter on behalf of the House.

Proposal for Public Borrowing for completion of Irrigation projects in Maharashtra

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV (Maharashtra): Madam, first I thank you for accepting our proposal to write to the Prime Minister for conferment of Bharat Ratna on Maulana Abul Kalaam Azad and on our great patriot, Netaji Subhas Chandra Bose. I fully associate myself with the sentiments expressed by Mr. Pramod Mahajan. Now I come to my special mention.

My special mention is about Maharashtra State—our proposal for public borrowing through project-specific bonds for accelerating the completion of irrigation projects in Maharashtra. Maharashtra has an ultimate target of 52.61 lakh hectares to be brought under surface irrigation as per the Irrigation Commission's Report of 1962. By the end of the Seventh Five Year Plan 26.18 lakh hectares of land was brought under surface irrigation. Up till now 19 major projects, 174 medium and 1500 minor irrigation projects have been completed. From the beginning of the First Five Year Plan the total investment done up to 31st March, 1990 was Rs. 4,300 crores. . Presently 37 major, 74 medium and 460 minor irrigation projects are under various stages of execution. In the Eighth Five Year Plan the total expenditure